

[27 April, 2001]

RAJYA SABHA

## RAJYA SABHA

*Friday, the 27th April, 2001/7 Vaisakha, 1923 (Saka)*

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

#### Gujarat Relief Measures

\*601. SHRI SUKHDEV SINGH LIBRA†:

SARDAR GURCHARAN SINGH TOHRA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the total amount of contribution to the Prime Minister's National Relief Fund, as on date, in connection with Gujarat earthquake victims;

(b) the amount released for Gujarat earthquake victims so far;

(c) whether some MPs from Gujarat have complained to Government regarding criminal neglect in relief and rehabilitation work in Kutch region; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

#### Statement

(a) The corpus of Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) is constituted entirely with voluntary contributions and disbursements from the Fund are entirely at the discretion of the Prime Minister.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sukhdev Singh Libra.

(b) Government of India have so far released Rs. 830 crores to the State from the National Calamity Contingency Fund (NCCF) for relief and rehabilitation.

(c) and (d) Distribution of relief and rehabilitation on the ground is the responsibility of the State Government. However, available communications from the Hon'ble Members of Parliament from Gujarat either relate to suggestions for improving and intensifying relief and rehabilitation measures or seek help for specific areas.

**श्री सुखदेव सिंह लिंग्रा:** सभापति महोदय, गुजरात में भूकम्प प्रभावित इलाकों के पुनर्वास और भूकम्प पीड़ित लोगों की सहायता के लिए सरकार की ओर से, भारतीय जनता की ओर से और विदेशों से इतनी मदद आ रही है या आ चुकी है जिससे सभी प्रभावित शहर और कस्बे एकदम नए बनाए जा सकते हैं और भूकम्प पीड़ितों को अच्छी फाइनैशियल ऐड दी जा सकती है जिससे कि वे अपना कारोबार शुरू कर सकें। लेकिन, सभापति जी, अक्सर अखबारों और टीवी में ऐसी खबरें आती रहती हैं कि प्रभावित इलाकों में राहत कार्य नहीं हो रहे और दी गई मदद का भिस-यूज हो रहा है। जो मकान भूकम्प की वजह से गिरने वाले हैं, उनकी केवल मरम्मत कराकर लोगों को उनमें बसने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह कल ही टीवी के 'आज तक' चैनल में दिखाया गया है।

मैं अपने प्रश्न के (ए) भाग के रूप में सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई वाच डॉग टाइप कमेटी का गठन किया गया है जो भूकम्प पीड़ित राहत कार्य की देख-रेख कर सके? अगर ऐसी कोई कमेटी है तो उसका गठन कब हुआ, उसके मैम्बर कौन-कौन हैं और उस कमेटी की अभी तक कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं?

मेरे प्रश्न का (बी) भाग है, अगर नहीं तो क्या सरकार...

**श्री सभापति:** आपने दूसरा सवाल भी तो करना है।

**श्री सुखदेव सिंह लिंग्रा:** सर, वी भाग है

**श्री सभापति:** आपने दूसरा सवाल नहीं करना, पहले सवाल में ही सारे सवाल कर देंगे आप?

**श्री सुखदेव सिंह लिंग्रा:** ठीक है, सर।

**श्री नीतीश कुमार:** सभापति जी, गुजरात में भूकम्प के बाद वहां के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से, विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों की तरफ से और दूसरे मुल्कों से भी बड़ी मात्रा में राहत सामग्री और धन मुहैया कराया गया है। इस संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड में भी लोगों ने दान दिया है।

ગુજરાત સરકાર ને વહાં રાહત કે બાદ રિહેબલિટેશન ઔર રિકસ્ટ્રક્શન કે લિએ ભી કર્ડ પ્રકાર કે પૈકેજ ઘોષિત કિએ હૈન્। કર્ડ સંગઠનોને યે કામ અપને જિમ્મે લિયા હૈ। ઇસમાં સરકાર કી તરફ સે ભી કામ હો રહા હૈ ઔર ગૈર-સરકારી સંગઠનોની કી તરફ સે ભી કામ હો રહા હૈ। ગુજરાત સરકાર ને એક અધિકારી કા નિર્માણ કિયા હૈ। ચૂંકિ યહ વિષય ભી મૂલતા: રાજ્ય કા હૈ ઔર જવાબદેહી ભી મૂલતા: રાજ્ય કી હૈ, ઇસલિએ હમ લોગોની ભૂમિકા ઉન્હેની મદદ પહુંચાને કી હૈ લેકિન ધરતી પર કામ કરને કી જો જવાબદેહી હૈ, વહ ઉન્હીની કી હૈ ઔર વે બહુત હી બેહતર ઢંગ સે કોઆર્ડિનેટ કરકે ઇસ કામ કો કર રહે હૈન્ ઔર મુખ્ય મંત્રી કી દેખ-રેખ મેં ભી એક કમેટી વહાં કામ કર રહી હૈન્।

**શ્રી સુખદેવ સિંહ લિલાંદ્રાઃ** સર, વાચ ડાંગ ટાઇપ કમેટી બનાને કે બારે મેં તો જવાબ આયા નહીં કી બનાઈ યા નહીં?

**શ્રી સભાપતિ:** ઇન્હેની બતાયા હૈ કી એક કમેટી બનાઈ હૈ વહાં કે ચીફ મિનિસ્ટર કી દેખ-રેખ મેં।

**શ્રી સુખદેવ સિંહ લિલાંદ્રાઃ** સભાપતિ જી, મેરા દૂસરા સવાલ યાહું હૈ કી ભૂતપૂર્વ અમરીકી રાષ્ટ્રપતિ, શ્રી બિલ કિલંટન ને અપને ભુજ-કચ્છ દૌરે કે બાદ કિસ પ્રકાર કી સહાયતા દેને કા આશ્વાસન દિલાયા હૈ ઔર ઉસ પર ભારત સરકાર કા ક્યા રિએક્શન હૈન્?

**શ્રી નીતીશ કુમારાઃ** સર, જૈસા કી મૈને પહલે બતાયા હૈ કી વિભિન્ન સંસ્થાઓની કી તરફ સે, દેશ કે અંદર સે ઔર દેશ કે બાહ્ય સે ભી મદદ મિલ રહી હૈ ઔર કર્ડ સ્થાનોની પર લોગોને ને ગાંધી અપને હાથ મેં લિએ હૈન્, ઉસકે રિહેબલિટેશન કા કામ અપને જિમ્મે લિયા હૈ ઔર ઇસ સિલસિલે મેં ગુજરાત સરકાર કોઆર્ડિનેશન કા કામ કર રહી હૈન્। હમ લોગોની પાસ બાહ્ય સે જો ભી સહાયતા આઈ, ઉસકે વહાં પહુંચાને કે લિએ જો કોઆર્ડિનેશન કી વ્યવસ્થા કી આવશ્યકતા થી, વહ યથાં સે કી ગઈ।

**શ્રી રમા શંકર કૌશિક:** સભાપતિ મહોદય, મંત્રી જી ને અપને ઉત્તર મેં કહા હૈ કી પ્રધાનમંત્રી રાહત કોષ કી સંગ્રહ નિધિ કા ગઠન પૂરી તરફ સે સ્લેચ્ચિંગ અંશદાનોને સે હોતા હૈ। મૈં માનનીય મંત્રી જી સે યા નિધેદન કરના ચાહતા હું કી ઇસકે લિએ ખાસ તૌર સે ઐલાન કિયા ગયા થા કી ભૂકંપ પીડિતોની સહાયતા કે લિએ પ્રધાનમંત્રી કોષ મેં સહાયતા દીંગિએ। ઇસકે અતિરિક્ત આયકરદાતાઓને પર 2 પરસેટ અધિભાર લગાયા ગયા થા ઔર વહ ઇસ આધાર પર લગાયા ગયા થા કી ભૂકંપ પીડિતોની સહાયતા કે લિએ આવશ્યક હૈ। મૈં માનનીય મંત્રી જી સે યા જાનના ચાહતા હું કી જો પૈસા લોગોને ને ભૂકંપ પીડિતોની સહાયતા કે લિએ દિયા હૈ ઔર જો જો પૈસા આપકો અધિભાર સે પ્રાપ્ત હુઅા હૈ, ક્યા વહ સારા કા સાથ પૈસા આપને ગુજરાત સરકાર કો પેજ દિયા હૈ યા ઉસકા નિયોજન કિયા હૈ? ક્યા યા યા કાર્યવાહી આપ સ્વયં કર રહે હૈન્?

**श्री नीतीश कुमार:** सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में लोग दान देते हैं। यह एक द्रृष्टि है और इसके माध्यम से विभिन्न कार्यों के लिए यह पैसा दिया जाता है। गुजरात के लिए भी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से पैसा दिया गया है, यह सार्वजनिक जानकारी का विषय है लेकिन जहां तक 2 प्रतिशत अधिभार से जो पैसा आया, उसका सवाल है, वह पैसा NCCF में जाएगा और NCCF के माध्यम से वह पैसा गुजरात को मिलेगा। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के पार्ट बी के उत्तर में बताया है, अब तक NCCF से 830 करोड़ रुपया रिलीज़ किया जा चुका है। मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि यह जो अधिभार लगाया गया है, चूंकि यह गुजरात को ध्यान में रखकर लगाया गया है, इसलिए इसमें जो भी पैसा आएगा, वह सारा पैसा गुजरात को ही दिया जाएगा।

**श्री अनन्तराय देवशंकर दबे:** सभापति महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट के 3 पहलू हैं—प्लड, साइक्लोन और सूखा। ये तीनों पहलू कच्छ पर लागू होते हैं और अब उसमें भूकंप भी शामिल हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां 2 साल पहले बाढ़ की स्थिति थी, पिछले साल सूखा था और इस साल भी बारिश नहीं हुई है। महोदय, वहां के किसान 2 साल से सूखे की वजह से बहुत परेशान हैं और भूकंप के कारण बहुत से गांवों में किसानों के मकान गिर गए हैं। तो क्या इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मंत्री महोदय अपने डिपार्टमेंट की ओर से कच्छ के किसानों की मदद के लिए कोई स्पेशल योजना बनाएंगे?

**श्री नीतीश कुमार:** सभापति महोदय, गुजरात में भूकंप आने से पहले पिछले 2 वर्षों से सूखे की स्थिति है और इससे निपटने के लिए अलग से सहायता दी जा रही है। महोदय, सूखे की समस्या से निपटने के लिए NCCF से पहले ही 85 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। यह कैलेपिटी फंड का जो सेंट्रल शेयर है, उसके अतिरिक्त है। अब गुजरात में भूकंप आने के बाद वहां की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसलिए वहां काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत अनाज दिया जा रहा है और कई अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। वहां का जो पूर्वी इलाका था, उसका क्रॉप इंश्योरेंस का मामला भी अब सैटल कर दिया गया है, अभी 3-4 दिन पहले वह मामला सैटल कर दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के विभिन्न महकमों की ओर से जो कुछ भी किया जा सकता है, वह किया जा रहा है और हर चीज में वहां मदद दी जा रही है।

**SHRI SANTOSH BAGRODIA:** Mr. Chairman, Sir, I will put some specific questions. If the hon. Minister gives specific replies to those questions, I will appreciate it. He has mentioned that the corpus of Prime Minister's National Relief Fund comprises entirely of

voluntary contributions. I would like to know from the hon. Minister whether some donations have been received specifically for the Gujarat Relief Fund, under this Fund. He has specifically mentioned that this is meant for the Gujarat Relief Fund. If so, how much amount has been received and how much amount has been given for this specific purpose. Similarly, Sir, he has mentioned about the 2% surcharge. The total estimate in the Budget was about Rs. 2400 crores. I would like to know whether the Government has realised, only Rs. 830 crores, or, they have realised more and disbursed less, or, whether they are going to disburse more as and when they realise it. If we can get the specific information, instead of a general reply on this point, it will be highly appreciated.

**श्री नीतीश कुमार:** जहां तक प्रधान मंत्री नेशनल रिलीफ फंड का सवाल है उसके संबंध में सरकारी तौर पर कोई जानकारी मेरे पास नहीं है क्योंकि वह एक द्रस्ट है और किसी विभाग के जुम्मे वह काम नहीं है। वोल्यूटरी डॉनेशन जो आते हैं प्रधान मंत्री जी द्वारा उससे विपदा की स्थिति में या जो इंडिविज्युअल बीमार होता है उसके इलाज के लिए या और प्रकार की कई परिस्थितियों में मदद की जाती है। इसके बारे में आम जानकारी लोगों को है और इसके संबंध में जो सूचनाएं हैं वह वेब साइट पर भी उपलब्ध हैं। गुजरात के संबंध में प्रधान मंत्री ने उदारतापूर्वक लोगों से जो मदद की अपील की है उसका असर सिर्फ़ प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ही धन नहीं आया बल्कि हर स्तर पर लोगों ने दान दिया है और वह सब गुजरात के काम में लगाया जा रहा है। जो गुजरात के काम के लिए एन०सी०सी०एफ० में, जैसा मैंने पहले कहा है दो प्रतिशत अधिभार लगाया गया, सरचार्ज लगाया गया, से जो पैसा आएगा वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वह पैसा गुजरात में ही जाएगा। अभी जो राशि रिलीज की जा चुकी है उसका मैंने उल्लेख किया। इसके बाद और राशि रिलीज की जा रही है।

**श्री संतोष बागड़ोदिया:** कितना आया, कितना गया?

**श्री नीतीश कुमार:** यह तो पूरे तौर पर जो आकलन है वह आपके पास उपलब्ध है। सेकिन जो कुछ भी पैसा उसमें कुल मिला कर के आएगा वह पैसा गुजरात को ही मिलेगा, यह बात साफ तौर पर वित्त मंत्री जी ने बतला दी है।

**SHRI B.P. SINGHAL:** Sir, we have been having wars almost at an interval of 10 years, calamities almost every year, big calamities almost every three years. What we need is a permanent fund for this. This time, the Government has levied a 2% surcharge to help the

earthquake-affected people of Gujarat. I would like to know, is the Government considering levying the 2% surcharge on a permanent basis on all tax-payers so that we could have enough reserves for both, the defence personnel who are killed in wars and the calamity-affected people. Because, whatever reserves there may be, fall woefully short when the actual calamity takes place. And then the Government goes on begging and everybody is trying to raise money. That kind of a thing could be avoided if we raise a permanent fund so that we have enough money to deal with the calamities which take place every year.

**श्री नीतीश कुमार:** सभापति महोदय, इलेविथ फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशंस के आधार पर, उनकी अनुशंसाओं के आधार पर विभिन्न राज्यों के कैलेमिटी रिलीफ फंड निर्धारित हैं। उसमें से तीन चौथाई केन्द्र सरकार देती है और एक चौथाई राज्य सरकारों को देना होता है। उसके अतिरिक्त जो बड़ी विपदाएं आएंगी उसका मुकाबला करने के लिए अगर जो स्टेट का कैलेमिटी फंड है जिसमें केन्द्र तीन चौथाई मदद देती है उसमें वह परिस्थितियों से निबटने में सक्षम नहीं हो तैसी स्थिति में एक नेशनल कैलेमिटी कंटिन्यूरी फंड की भी व्यवस्था की गई है। इलेविथ फाइनेंस कमीशन के हिसाब से शुरू में केन्द्र सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया डाला गया था। इलेविथ फाइनेंस कमीशन ने ही कहा है कि इसमें जिस तरह से खर्च होता जाए उसको रिकूप करते जाइए सरचार्ज लगा करके सेंट्रल टेक्सेज पर और उसी व्यवस्था के अंतर्गत सरचार्ज लगाया गया है और उसको रिकूप किया जाएगा। एन०सी०सी०एफ० से पिछले वर्ष 2000-2001 साल में सूखा प्रभावित राज्यों को भी मदद दी गई है और आगे भी जो इलेविथ फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशंस है उसके हिसाब से एन०सी०सी०एफ० से जरूरत पड़ने पर मदद की जाती रहेगी।

**श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल :** सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि क्या परमानेट बैंकिंग पर ऐसी स्कीम शुरू करने का इहदा है या करना चाहेगे?

**श्री नीतीश कुमार:** ऐसा फिलहाल कोई इहदा नहीं है क्योंकि फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशंस के आधार पर कैलेमिटी रिलीफ बैनेजमेंट होता है और उसने यह व्यवस्था कर रखी है। फिलहाल वह व्यवस्था पर्याप्त मालूम पड़ती है।